ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेज:3

पोल्ट्री फार्मों के लिए अब सीपीसीबी की नयी गाइडलाइन

रविवारीय, 29 अगस्त - 04 सितंबर 2021 वर्ष- तीन, अंक -03, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य:5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

राज्यपाल ने दी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि

रांची :राज्यपाल रमेश बैस ने विश्व हॉकी जगत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति को स्मरण करते हुए नमन किया एवं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को समर्पित 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के अवसर पर देश के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व में माँ भारती का गौरव बढ़ाने में मेजर ध्यानचंद का जुनून व संकल्प सदैव प्रेरणीय रहेगा।

टोंगिया समुदाय: 10,000 हेक्टेयर में वन लगाया अब वही लोग खदेड़े जायेंगे?

शिवालिक रेंज में रहने वाले पारंपरिक वनवासी समुदाय ने 10,000 हेक्टेयर में दशकों से जंगल लगाने के साथ-साथ उनकी रक्षा भी की है।पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के ठीक तरीके से लागू न होने की वजह से ये समुदाय अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि जंगल से आदिवासियों और वनवासियों को निकाला गया तो वन्यजीव और इंसानों के बीच टकराव बढ़ सकता है।

उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में टोंगिया को वनवासी समुदाय के तौर पर जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ी के बाहरी इलाके में जंगल लगाने का श्रेय भी इसी समुदाय को जाता है। एक अनुमान के मुताबिक शिवालिक में अंग्रेजों के समय इन्होंने 10 हजार हेक्टेयर जमीन पर जंगल लगाया और उसे बचाकर रखा। इस समुदाय ने कृषि-वानिकी या एग्रोफॉरेस्ट्री को वन संरक्षण कानून,1980 के आने से पहले ही अपना लिया था। यह कानून समुदायों को जंगल के प्रबंधन से रोकता है। ''अब इन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखाने और घरों को तोड़ देने जैसी धमकियां दी जा रही है।

पहले भी झारखंड में निवेश और रोजगार पैदा करने के ढेरो वादे और दावे किये गये, पर धरातल पर कुछ नहीं उतरा, क्या

इन्वेस्टर्स मीट से बदलेगा झारखंड?

वरीय संवाददाता

दो दशक के झारखंड में सरकारें बदलती रही हैं और हर सरकार झारखंड को तेज विकास के रास्ते पर ले जाने का वादा करती रही है। लेकिन यह सर्वविदित है कि झारखंड अलग राज्य जिन उम्मीदों आकांक्षाओं को लेकर बनाया गया उसकी कसौटी पर आज तक कोई भी सरकार खड़ी नहीं उतरी। राज्य में आज भी पलायन जारी है, रोजी रोजगार ही नहीं अच्छी शिक्षा के लिये भी युवा राज्य से बाहर का रूख करते हैं।

अविभाजित बिहार को भारत का रीढ़ राज्य कहा जाता था क्योंकि तब खनिजों और प्राकृतिक संपदाओं वाला समृद्ध झारखंड बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था। आज यह क्षेत्र एक अलग राज्य बन गया है उसके बावजूद यह औद्योगिक और खनिजों से परिपूर्ण राज्य विकास के दौड़ में पिछड़ा ही हुआ है। पिछली पूर्ण बहुमत की सरकार में भी तामझाम के साथ एमओयू होते रहे, निवेश के लिये बड़े और भव्य आयोजन किये गये, उनका खूब प्रचार प्रसार किया गया, पर जमीन पर ठोस कार्य नहीं हुआ।

वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सूरत बदलने के प्रयास में दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। दावा है कि इससे राज्य का तेज विकास होगा, रोजगार के बेशुमार अवसर बनेंगे। इस बार हम उम्मीद करें कि इस भव्य आयोजन का प्रतिफल ठोस रूप से जमीन पर दिखे और झारखंड अपने निर्माण की उम्मीदों को पूरा करे।

- **दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट आनेवाले दिनों में झारखण्ड में 10,000 करोड़ के निवेश के साथ करीब 1.5 लाख रोज़गार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा.**
- **उद्योग में अगर निवेशक अपने उद्योग के कुल मानव बल में राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 35 % हुनरमंद लोगों रोजगार देंगे तो राज्य सरकार नीति के तहत दिए जा रहे प्रोत्साहन और प्रावधानों के अतिरिक्त निवेशकों को लाभ देगी**
- **टाटा स्टील अगले तीन वर्ष में तीन हजार करोड़, डालमिया भारत ग्रुप 758 करोड़, आधुनिक पावर 1900 करोड़ और सेल द्वारा गुवा माइंस में अगले तीन वर्ष में चार हजार करोड़ एवं प्रेम रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़ का निवेश एवं एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेगा।**
- **मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योग सचिव और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने करीब 10, 000 करोड़ निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया**
- **संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास के राह पर ले जाने का हो रहा प्रयास**
- **देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जल्द**
- **रोजगार सृजन और झारखण्ड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ले जाने का लक्ष्य**

सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, ये कदम अब थमेंगे नहीं

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नई दिल्ली स्थित होटल ताज में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लोकार्पण समारोह कही कि राज्य सरकार निवेशक साथियों का सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यहां के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए झारखण्ड को विकास की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। ये कदम अब थमेंगे नहीं।

झारखण्ड में माइंस और मिनरल के इर्द गिर्द बातें सोची गई। ये तो पूर्व की तरह कार्य करती रहेंगी। इस-ाके अतिरिक्त टूरिज्म, एजुकेशन, रिन्यूबल एनर्जी, फ़ूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। रिन्यूबल एनर्जी में हम बड़ा प्रोजेक्ट ले कर आ रहे हैं। झारखण्ड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करेगा। हमारी सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए, उद्योग का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। हमारा प्रयास झारखण्ड को अग्रणी राज्यों में ले जाने का है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से कहा कि झारखण्ड में उद्योग को लेकर आपके कई सुझाव हमें मिले हैं। इसी का नतीजा है कि आज अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार हुई है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आप लोगों ने झारखण्ड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। एमओयू हो रहा है। कई स्वीकृतियां भी प्रदान की गयी हैं।

शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग कर इसका लाभ लोगों को नहीं दे पाए हैं। हमारे पास जो खनिज संपदा का भंडार है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य में पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। प्रसिद्ध नेतरहाट स्कूल हमारे राज्य में ही है। जिसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ने देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिया है। इसके अतिरिक्त इजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में भी झारखण्ड अच्छा कर रहा है। झारखण्ड शिक्षण और तकनीकी संस्थानों को भी बढ़ावा देगा।

टीम ग्रीन ने पहाड़ी मंदिर पर 1111 पेड़ लगाने का लक्ष्य हासिल किया

टीम ग्रीन के सदस्य और स्थानीय लोग पहाड़ी पर पौधारोपण करते हुये

संवाददाता

रांची : राजधानी रांची का गौरव और पहचान है पहाड़ी मंदिर। इसे फांसी टुंगरी और रिची बुरू नाम से भी जाना जाता है। भूगर्भवेत्ताओं ने इसे हिमालय से पुराना बताया है। शहर के बीचोबीच स्थित यह पहाड़ी रांची आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। कई पुराने बाशिंदों का कहना है कि एक बार जो रांची आकर पहाड़ी पर चढता है और चोटी पर स्थित शिव मंदिर में जाता है उसका लगाव आजीवन रांची से बन जाता है और वह विश्व में कहीं भी घूमे दुबारा उसे रांची आना ही पड़ता है।

लेकिन हाल के कुछ सालों में प्रदूषण, अतिक्रमण, घातक निर्माण के कारण रांची की पहचान रहे इस पहाड़ी से जंगलों का विनाश होता गया और अपरदन से इसकी मिट्टी भी जहां तहां से धंसने लगी। ऐसे में रांची में पर्यावरण प्रेमियों की संस्था **टीम ग्रीन** ने रांची पहाड़ी को फिर से हरा भरा और संवारने का बीड़ा उठाया और अपने दो दिवसीय (28 और 29 अगस्त) मेगा प्लांटेशन ड्राइव अभियान के दौरान 1111+ पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त किया। साथ ही, टीम ग्रीन ने अपनी स्थापना के 2 वर्षों के भीतर 10,000 पौधे रोपने की उपलब्धि हासिल की है। टीम ग्रीन के वृक्षारोपण का उद्देश्य मंदिर पहाड़ी पर वृक्षारोपण को बढ़ाना है ताकि मिट्टी के कटाव को कम किया जा सके और ढलान स्थिरीकरण को बढ़ाया जा सके। 120+ स्वयंसेवकों और 80+ रांची के नागरिकों की भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम ऊर्जा और उत्साह से भरा था। प्रबंधन और तैयारी बहुत अच्छी तरह से की गई थी, जिसमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखा गया था, सभी ने मास्क पहने थे और सभी बिंदुओं पर मार्गदर्शन के लिए स्वयंसेवक मौजूद थे। बदलते मौसम और भारी बारिश के बीच ग्राउंड टीम ने पौधे लगाना जारी रखा। एसडीओ दीपक दुबे, भाजपा विधायक सीपी सिंह और भाजयुमो के शशांक राज ने अभियान का दौरा किया और सभी को नेक ग्रीन कॉज के लिए बधाई दी। उन्होंने पौधे भी रोपे और इस कार्य में अपना समर्थन देने का वादा किया। दूसरे दिन, कार्यक्रम में रांची के नागरिक भी शामिल हुए और पूरी टीम द्वारा किए गए कार्यों की सभी ने सराहना की । टीम को भविष्य में इस तरह के कार्यों का निमंत्रण भी मिला। छात्रों, पेशेवरों, परिवारों, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय निवासियों, मीडिया घरानों, अधिकारियों ने भी पेड़ लगाया। *पेज चार भी देखें*

स्कूली बच्चों में कोरोना रोकने में मास्क ज्यादा कारगर

शोध बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बच्चों के लिए मास्क ही सबसे आसान और कारगर तरीका सिद्ध हुआ है

कोरोनावायरस की मार कहने के लिए तो पूरी दुनिया पर पड़ी है लेकिन इनमें से सबसे अधिक संवेदनशील तबका बच्चों का है। यूनीसेफ की यदि रिपोर्ट में आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वायरस की मार बच्चों पर ही पड़ी है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में 1.8 अरब बच्चे किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। अब जबकि भारत सहित दुनियाभर के कई देशों में स्कूल-कॉलेज खोल दिए गए हैं। ऐसे में यह एक बड़ा सवाल उठता है कि कोरोना वायरस से उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं? और क्या सरकारों द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त हैं? क्योंकि अब तक 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है।

स्कूलों में सुरक्षा से जुड़े इस सवाल पर न्यूयार्क टाइम्स ने एक अध्ययन किया। उसमें इस बात का पता लगाया गया कि मास्क पहनने और नहीं पहनने से वायरस के बढ़ने की संभावना कितनी होती है? अध्ययन में यह बात निकलकर आई है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बच्चों के लिए मास्क ही सबसे आसान और कारगर तरीका है।

7,000 से अधिक बच्चों व व्यस्कों पर यह अध्ययन किया गया। ये सभी लोग एक स्कूलों में कोरोना वायरस से संक्रमित थे। अध्ययन में पाया गया कि इन लोगों के निकट संपर्क में आने के कारण 40,000 से अधिक लोगों को क्वारटाइन में रहना पड़ा।अध्ययन के दौरान किए गए । परीक्षण से पता चला कि इनमें से केवल 363 बच्चे और वयस्क ही सीधे तौर पर कोरोनावायरस से संक्रमित हुए। संचरण की यह कम दर स्कूलों में लगातार मास्क पहनने के कारण संभव हुई। संक्रमित व्यक्ति और करीबी संपर्क वाले दोनों ने मास्क पहना था। इसके अलावा स्कूल ने कोरोना वायरस के लिए लगातार परीक्षण की व्यवस्था की हुई थी और स्कूल के वेंटिलेशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर खर्च किया गया था। अध्ययन में पता चला कि जब स्कूलों ने मास्क की अनिवार्यता लागू की, तब कोरोनोवायरस की स्कूल में संचरण दर कम थी। इसके विपरीत इजराइल में एक स्कूल में बिना मास्क और उचित सामाजिक दूर के कारण कोरोना वायरस अधिक तेजी से फैला।अध्ययन में कहा गया कि अमेरिका के टेक्सास और फ्लोरिडा राज्यों में कोरोना वायरस बच्चों, किशोरों और वयस्कों के बीच बड़े पैमाने पर बिना मास्क और सामाजिक दूरी को नजरअंदाज करने के कारण आसपास के समुदायों में फैलने की संभावना अधिक देखी गई। ध्यान रहे कि अमेरिका में इसी सामुदायिक प्रसार की संभावना के मद्देनजर मार्च, 2020 में स्कूलों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे।

अध्ययन में कहा गया है कि इन बातों ये यह स्पस्ट होता है कि मास्क लगाना और न लगाना कोरोना वायरस के प्रसार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कारक है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में मास्क की अनिवार्यता नहीं होगी, उनमें अधिक कोरोना वायरस का संचरण होगा। *अनिल अश्विनी*

भोला सिंह बने एनसीएल के सीएमडी

संवाददाता

रांची : 26 अगस्त को 'लोक उद्यम चयन बोर्ड (पब्लिक इंटरप्राईजेज सलेक्शन बोर्ड)' द्वारा आयोजित साक्षात्कार में भोला सिंह के नाम की अनुशंसा नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के सीएमडी के रूप में किया गया है। वर्तमान में भोला सिंह सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) में निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना)के रूप में वर्ष 2019 से कार्यरत हैं।

ज्ञातव्य है कि भोला सिंह का लगभग 34 वर्षों का लंबा अनुभव रहा है जिस दौरान उन्होंने देश एवं विदेश की प्रतिष्ठित सार्वजनिक एवं नीजी उपक्रमों में अपना योगदान दिया है। भोला सिंहने आईआईटी, खड़गपुर से माईनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1987 में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल से की। भोला सिंह ने 2008 में एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना योगदान दिया था। उसके उपरांत इन्होंने सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के शासन पावर लिमिटेड में परियोजना निदेशक के रूप में सफलतापूर्वक योगदान देते हुए देश के पहले अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (6X660MW) में कार्य करने का गौरव प्राप्त किया। इनके नेतृत्व में शासन परियोजना को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये राष्ट्रपति ने वर्ष 2017 में नेशनल सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया था।

प्रदूषण से मुंबई की इस बस्ती में 40 साल में ही आ जाता है बुढ़ापा

अपेक्षिता वार्ष्णेय

महानगरों में चकाचौंध के बीच गरीबी ,प्रदूषण और आजीविका के लिये संघर्ष का एक ही चित्र होता है जिसे शायद ही कभी दिखाया जाता है। माया नगरी मुंबई भी अन्य महानगरों की तरह प्रदूषित और हलकान है और अन्य शहर भी तरक्की के एवज में अपने अंदर स्लम एरिया भी बना रहे हैं। देवनार में मुंबई शहर का कचरा इकट्ठा होता है। 134 हेक्टेयर में फैले इस डंपिंग ग्राउंड पर 9,000 मीट्रिक टन कचरा जमा होता है, जिससे पास की बस्ती में लोगों का जीना दूभर हो गया है।

बस्ती में रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रदूषण का इतना घातक असर हो रहा है कि यहां के लोगों का औसत जीवनकाल 39 वर्ष ही रह गया है। जबकि महाराष्ट्र में शहरी लोगों का औसत जीवनकाल 73.5 साल आंका गया है। मुंबई के कचरा प्रबंधन के लिए राजनीतिक इच्छा-शक्ति भी जरूरी है। हाल ही में नगर निगम ने कचरा चुनने वालों को गीले और सूखे कचरे को अलग करने का ठेका देने का निर्णय लिया है। जबकि कई सालों से यह कहा जा रहा है कि घरों में ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना सबसे बेहतर उपाय है।

सूरज उगने से पहले जगकर तैयार होती मानसी दिघे (बदला हुआ नाम) का दिन बेहद संघर्षों से भरा होने वाला है। साड़ी ठीक कर अपने बाल बनाते हुए दिघा की मंजिल है मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड-देवनार। रोज 20 से 25 किलोमीटर की थकान भरी पैदल यात्रा से दिघे इतना कचरा भी इकट्ठा नहीं कर पाती कि उसे बेचकर 100 रुपए से अधिक की कमाई हो सके। लोहा, प्लास्टिक और कांच के टुकड़े 20 रुपए प्रति किलो बिक जाते हैं। मुंबई की एक करोड़ से अधिक आबादी हर दिन 9,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करती है जिसे 234 एकड़ में फैले डंपिंग ग्राउंड में भेजा जाता है। यहां कचरे का अंबार 18 से 20 मंजिला इमारत जितना है। आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोग यहां से काम लायक कचरा चुनकर अपनी रोजी-रोटी भी चलाते हैं।

''हमारे लिए तो यह कचरे का अंबार सोने की खान जितना महत्व रखता है,'' दिघे कहती हैं। ''कचरा बीनने के लिए ग्राउंड में घुसना है तो नगर निगम के कर्मचारियों को कुछ पैसा खिलाना पड़ता है,'' वह कहती हैं। हाल ही में मुंबई के नगर निगम ने घोषणा की है कि कचरा चुनने वालों को डम्पिंग ग्राउन्ड इत्यादि में कचरा अलग करने का ठेका दिया जाएगा। जबकि यह कहा जाता रहा है कि कचरा को घर में ही अलग करना सबसे बेहतर उपाय है।सरकार के इस कदम से कितना फायदा होगा यह तो भविष्य की गर्भ में है पर इस बहाने इस डंपिंग ग्राउंड के आस-पास रहने वाले लोगों की हालचाल जानें। मुंबई में इन बस्तियों में रहना सबसे सस्ता विकल्प है, इस वजह से प्रवासी मजदूर और कचरा बीनने वाले लोग यहां रहने को मजबूर हैं।स्थानीय लोगों की मानें तो देवनार के लोगों का जीना दूभर हो रखा है। यहां के कचरे से, सड़ने के बाद, मिथेन गैस निकलता है जिसकी वजह से यहां बार-बार आग लगने की घटनाएं भी होती रहती है। बदबू की समस्या भी बनी रहती है। नगर निगम इससे निपटने के लिए कुदरती तरीके निकालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हाल ही में एक टेंडर भी निकाला गया। आसपास के लिए धुएं और बदबू की वजह से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिससे उनका जीवनकाल घट रहा है।

विकास के नाम पर झारखंड की खुबसूरती न बिगड़े

झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में इमर्जिंग झारखंड नाम से इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। इसमें राज्य में निवेश के लिये बड़े- बड़े उद्योगपतियों को न्यौता गया है और झारखंड में बेहतर निवेश का माहौल प्रस्तुत किया गया है। एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते झारखंड को विकास के पथ पर ले जाना मुख्यमंत्री का कर्त्व्य और दायित्व दोनो है। इसलिये वह प्रयासरत हैं।

बिना निवेश, उद्योग धंधों और बिना निर्माण के राज्य में रोजगार और समृद्धी नहीं आ सकती। झारखंड तो वैसे भी अपने निर्माण के दो दशकों के बाद भी पिछड़े हुये राज्य में हीं आता है।

मुख्यमंत्री को इस बात का भी विशेष खयाल रखना होगा कि बाहर की कंपनियां, उद्योगपति राज्य की संपदा से आकर्षित होकर आयें तो, पर विकास के नाम पर झारखंड के पर्यावरण को अपूरणीय क्षति न पहुंचायें। वैसे भी झारखंड की खनिज संपदा पूरे विश्व को ललचाती है। पहले से भी राज्य में जो उद्योग धंधे हैं उन्होंने झारखंड में पर्यावरण का कभी कोई खयाल नही रखा है। दामोदर नदी का हश्र हमारे सामने है। पत्थर और क्रशर माफियाओं ने राज्य की पहचान रहे पहाड़ियों को काट काट कर बहुत नुकसान पहुंचाया है।

झारखंड में तकरीबन 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है और राज्य के 32 प्रतिशत से कुछ अधिक भूभाग पर वन हैं। झारखंड की आबोहवा ऐसी है कि एक सर्वे के मुताबिक यह फूलों की खेती के लिये सबसे उपयुक्त है, यहां स्ट्राबेरी तक की भी अच्छी उपज हो सकती है। राज्य में पर्यटन की इतनी असीम संभावनायें हैं कि हम कश्मीर तक को टक्कर दे सकते हैं। हमारी नदियां, पहाड़, जंगल, झीलें झरनें किसी स्वर्गिक सुंदरता का आभास कराते हैं। इसके अलावा अगर शोध हों तो झारखंड में प्रागैतिहासिक जगहों की भी भरमार है जो पर्यटन को चार चांद लगा सकते हैं।

ऐसे में हमें इन बिंदूओं को लेकर विकास का खाका खींचना होगा, अन्यथा उद्योगपतियों को राज्य की खुबसूरती से क्या लेना देना, वो तो सिर्फ झारखंड का दोहन ही करेंगे।

झारखंड में रिकार्ड में 32 प्रतिशत से अधिक वन संपदा है, पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारी राजधानी रांची देश के सबसे कम हरियाली वाले राजधानियों में शर्मनाक रूप से शुमार है। हमारे यहां प्रसिद्ध सारंडा जंगल तो हैं, पर राज्य की आबो हवा हाल के कुछ सालों में बिगड़ी है। ऐसे में मुख्यमंत्री और सारे झारखंडियों का यह दायित्व भी बनता है कि राज्य का विकास हो ,पर वह पर्यावरण के साथ समन्वय के साथ हो। देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक झारखंड को अंधाधुंध विकास के नाम पर बिगाड़ने से भी बचाना होगा।

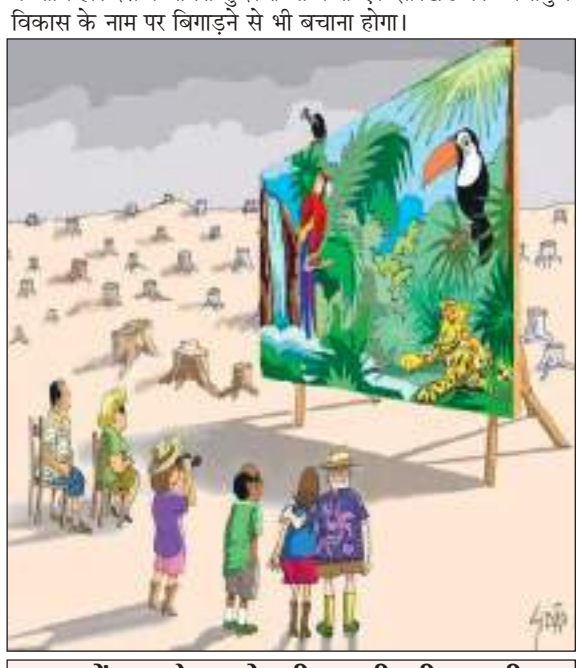

भारत में कमजोर तबके की 60 फीसदी आबादी पर मंडरा रहा है आपदाओं का खतरा

भारत में रहने वाले सबसे कमजोर तबके की 60 फीसदी आबादी पर बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जो 2040 तक इस वर्ग की करीब 71 फीसदी आबादी को अपनी जद में ले लेगा। यदि जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब परिदृश्यों (आरसीपी 8.5) के आधार पर देखें तो भारत में रहने वाले सबसे कमजोर और गरीब तबके की करीब 60 फीसदी आबादी पर बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जो 2040 तक कमजोर तबके की करीब 71 फीसदी आबादी को अपनी जद में ले लेगा। एक तरफ जहां यह वर्ग पहले ही गरीबी, भुखमरी, बीमारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के आभाव से जूझ रहा है, अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन की मार उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। यह जानकारी हाल ही में इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक (ईएससीएपी) द्वारा जारी एशिया पैसिफिक डिसास्टर रिपोर्ट 2021 में सामने आई है। वहीं यदि अपने सबसे करीबी पड़ोसियों की बात करें तो बांग्लादेश में रहने वाले गरीब तबके की 91 फीसदी आबादी पर आपदाओं का खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह नेपाल की 88 फीसदी, भूटान की 45 फीसदी, पाकिस्तान की 31 फीसदी और अफगानिस्तान में रहने वाला 19 फीसदी कमजोर तबका जलवायु परिवर्तन और आपदाओं की मार झेलने को मजबूर है।

यदि 2040 से 2059 की बात करें तो बांग्लादेश में रहने वाली इस वर्ग की करीब 98 फीसदी आबादी इस खतरे की जद में होगी। इसी तरह 2040 तक नेपाल की 90 फीसदी, पाकिस्तान की 79 फीसदी, भूटान की 43 फीसदी और अफगानिस्तान की 34 फीसदी कमजोर आबादी इन आपदाओं की मार झेलने को मजबूर होगी, जिसमें जलवायु में आ रहे बदलाव की भी बड़ी भूमिका होगी। यदि पूरे एशिया-पैसिफिक क्षेत्र को देखें तो ईएससीएपी द्वारा जारी इस रिपोर्ट से पता चला है कि यह क्षेत्र बीमारी, आपदा और जलवायु परिवर्तन के तिहरे खतरे को एक साथ झेलने के लिए मजबूर है, जो यहां की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहा है।

महानदी को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में खींचतान

महानदी के पानी को लेकर भारत के दो राज्य ओडिशा और छत्तीसगढ़ का विवाद काफी पुराना है। वर्ष 2016 में ओडिशा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नदी के ऊपर बन रहे बांध और बैराज इसे पूरी तरह सुखा देगें जिससे ओडिशा के लोग, उद्योग और अन्य चीजों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरणविद्, जागरूक नागरिक और सिविल सोसायटी संस्थाएं आरोप लगाती हैं कि दोनों राज्यों ने ही नदी के साथ न्याय नहीं किया है और अपने राजनीतिक और औद्योगिक फायदों के लिए इसका दोहन किया है। विद्वानों का मानना है कि दोनो राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों की जरूरत है।ताकि नदी पर समुदायों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

प्रगति प्रावा

ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित संबलपुर में हीराकुंड बांध का पानी दोनों राज्यों के लिए खींचतान का विषय बना हुआ है। ओडिशा का आरोप है कि महानदी पर बने बांधों में कम पानी वाले मौसम में भी पानी भरा रहता है जिससे नदी की धारा आगे रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पाती। पानी के बंटवारे को लेकर बने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (आईएसआरडब्ल्यूडी), 1956 के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल का कार्यकाल दो साल या रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक बढ़ा दिया गया है। ट्रिब्यूनल 11 मार्च, 2021 को अपना फैसला देने वाला था, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि राज्य किस फॉर्मेट में जानकारी साझा करेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यों के बीच में यह विवाद जुलाई 2016 में शुरू हुआ था। उस समय ओडिशा ने आरोप लगाया था कि महानदी पर बने बांध और दूसरी परियाजनाओं से इसकी धारा प्रभावित होती है। नदी के सूखने का खतरा है जिससे ओडिशा के आम लोग, किसान, उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में इस नदी पर तकरीबन दो हजार बांध और बैराज हैं। पर विवाद मुख्यत:12 बड़ी परियोजनाओं को लेकर है। ये हैं रविशंकर सागर बांध, हसदेव बांगो बांध, मुरूम सिल्ली बांध, तांदुला बांध, सोंदूर बांध, दुधवा जलाशय, घोंगा बांध, खारंग जलाशय, मोंगरा बैराज, मोनियारी टैंक और कोडर जलाशय। छोटी जल परियोजनाओं के तहत सिंचाई के नाम पर इन बांधों का निर्माण किया गया पर वास्तविकता यह है कि इस परियोजनाओं से उद्योग को पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा छह औद्योगिक बांध जिसमें साराडीह, कलमा, बसंतपुर, मिरौनी और शिवरीनारायण शामिल हैं, राज्यों के बीच के टकराव को और बढ़ा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इन छ: बराजों से सालाना 1405.66 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी उद्योग को दिया जाता है, जिससे नदी की पारिस्थितिकी तंत्र और इसके अस्तित्व को खतरा है।

महानदी के किनारे सैकड़ों उद्योग लगे हुए हैं। इससे ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 200 उद्योगों में पानी दिया जाता है। इसके अलावा नदी पर मछुआरे और किसान भी आश्रित हैं। छत्तीसगढ़ के बांध और बैराज से नदी के बहाव को खतरा है।ओडिशा के रहने वाले इंजीनियर ललित मोहन पटनायक के मुताबिक छत्तीसगढ़ में महानदी का कैचमेंट इलाका ओडिशा की तुलना में 10 फीसदी अधिक है। छत्तीसगढ़ में 30,000 एमसीएम पानी नदी से निकाला जाता है, वहीं ओडिशा में यह आंकड़ा 27,000 एमसीएम है। ओडिशा का अनुमान है कि जब छत्तीसगढ़ के सभी दो हजार बांध और बैराज पूरी तरह चालू हो जाएंगे, तो महानदी नदी न रहकर तालाबों में बदल जाएगी। गैर मानसून वाले मौसम में नदी में मात्र 829 एमसीएम पानी ही बचेगा। पटनायक कहते हैं कि गैर मानसून वाले मौसम में हीराकुंड बांध में एक तिहाई पानी ही बचता है। अगर छत्तीसगढ़ ने सभी बांध शुरू कर दिए तो इस बांध में पानी आएगा ही नहीं।

वर्ष 2018 में हुए एक अध्ययन 'महानदी: कोल रिच वाटर स्ट्रेस्ड' के अध्ययनकर्ता रंजन पांडा ने पाया कि ओडिशा सरकार ने जो आंकड़े जमा किए हैं उससे नदी को लेकर काफी निराशाजनक स्थिति दिखती है। छत्तीसगढ़ से ओडिशा में 19,237 एमसीएम पानी नदी से बहकर आता है, लेकिन भविष्य में पानी की मांग 23,651 एमसीएम होगी। इसका मतलब छत्तीसगढ़ कैचमेंट क्षेत्र से 4,414 एमसीएम पानी कम आएगा। हीराकुंड बांध में ओडिशा के कैचमेंट इलाके से 2,119 एमसीएम पानी आता है। अगर छत्तीसगढ़ ने बांधों के जरिए पानी रोक लिया तो ओडिशा को अपने कैचमेंट इलाके के पानी पर ही निर्भर रहना होगा। इस अध्ययन में पाया गया कि छत्तीसगढ़ के बांध की वजह से ओडिशा के हीराकुंड स्थित बांध में पानी नहीं बचेगा।

राजनीतिक विवाद

राज्यों के बीच पानी के विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार और छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच यह खींचतान चली। आरोप है कि दोनों पार्टियों ने इस विवाद का इस्तेमाल स्थानीय भावनाओं को हवा देने के लिए किया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस का शासन है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के योजना, नीति, कृषि और ग्रामीण विकास मामलों के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बताया कि सरकार पानी बचाने के सभी प्रयास कर रही है, जिससे नदी में पानी बढ़ेगा। शर्मा ने ओडिशा पर पानी का इस्तेमान न कर पाने का आरोप लगाया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वर्ष 2017 में एक बयान देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मात्र 4 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि ओडिशा 14 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल करता है। बचा हुआ 82 प्रतिशत पानी समुद्र में जाकर बेकार हो जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उस समय कहा था कि रमन सिंह विवाद को सुलझाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पटनायक ने विवाद सुलझाने के लिए ट्रीब्यूनल की मांग को जायज बताते हुए वर्ष 2018 में कहा था कि विवाद जारी है और दोनों राज्यों के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इसके बाद ओडिशा सरकार ने एक हलफनामे के माध्यम से तर्क दिया था कि केंद्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल बंटवारे पर त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, गैर-मानसून मौसम के दौरान ओडिशा को 1.74 मिलियन एकड़ फीट पानी छोड़ना चाहिए।

इस विवाद के बीच पर्यावरणविद् और जानकार मानते हैं कि किसी भी राज्य ने नदी को अविरल रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उनका आरोप है कि राज्यों ने न अपने नागरिक के साथ न्याय किया न ही नदी के साथ। दोनों राज्यों में खनन और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। विकास के लिए निवेश पाने के लिए दोनों राज्यों ने महानदी के पानी का इस्तेमाल किया। नदी में पानी का बहाव कम होने के बावजूद राज्यों ने इसकी वजह उद्योग, खनन या बिजली उत्पादन को नहीं माना। पर्यावरण कार्यकर्ता अजीत पांडा कहते हैं कि दोनों राज्यों ने 120 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें नदी के पानी की जरूरत होगी। हीराकुंड के पास ताप विद्युत संयंत्रों की भरमार है जो कि पानी सोखने वाले विशाल संयंत्र हैं। इस वजह से हीराकुंड के पानी पर काफी दबाव है। बिजली उत्पादन के संयंत्र न सिर्फ पानी सोखते हैं बल्कि इसकी वजह से गर्मी और प्रदूषण में भी काफी इजाफा होता है। इससे यहां की खेती भी प्रभावित हुई है, अध्ययन का कहना है। अध्ययन में सामने आया कि बिजली घरों से निकलने वाला फ्लाई ऐश या कोयले की राख से कई खेत खराब हो गए हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के दरलीपाली गांव में तीन कोयला खदान स्थित है। गांव के निवासी गोविंदा करली कहते हैं कि यहां के 93 परिवार को खनन कंपनी ने पुनर्वास का झूठा वादा कर विस्थापित कर दिया। ''हम यहीं रहे और पुनर्वास की मांग करते रहे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है,'' करली ने बताया।

रायगढ़ के पर्यावरणविद् रमेश अग्रवाल ने ओडिशा के आरोपों से सहमति जताई। वह कहते हैं कि बांध के लिए हजारो एकड़ में फैले जंगल को बर्बाद किया गया।इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के नागरिक भी नाराज हुए। दोनों राज्यों में पानी की कमी से फसल खराब हो रही है।

रोटी हो या चावल, सेतु का काम करती है दाल

दाल पर बने अनेक मुहावरे भारतीय जनमानस में दाल की अहमियत उजागर करते हैं। बता रहे हैं **पुष्पेश पंत**

यह दावा करना अतिश्योक्ति नहीं कि बिना दाल के हिंदुस्तान के खाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दाल-रोटी या दाल-भात रोजमर्रा के भोजन का पर्याय है। उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के निवासी चाहे गेहूं पसंद करते हों या चावल दोनों के बीच दाल सेतु का काम करती है। दाल न गलना, छाती पर मूंग दलना, यह मुंह और मसूर की दाल, आटे दाल का भाव पता चलना जैसे मुहावरे दाल की अहमियत उजागर करते हैं।

एक विद्वान ने देश के भौगौलिक नक्शे को ''दाल रेखा'' के अनुसार विभाजित किया है। पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण एक खास दाल की लोकप्रियता के आधार पर। इस मत के अनुसार कानपुर के आसपास काली दाल का साम्राज्य सिमट जाता है और पीली दाल का प्रभुत्व साफ नजर आता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे के बाद दाल सिर्फ दाल नहीं रहती सांबर में बदलने लगती है। यह विश्लेषण दिलचस्प तथा विचारोत्तेजक तो है पर इसे पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। काली छिलके वाली दाल जो आजकल दाल मखनी, दाल बुखारा, दाल महारानी नाम से भी पहचानी जाती है और पंजाबी ढाबों की वह सौगात है जो पांच तारा छाप होटलों की चहेती बन चुकी है।

पर पीली दाल का क्या अर्थ निकालें? अरहर, मूंग, चना, मलका, धुली उड़द यह सब पीले रंग की ही दालें हैं। रेस्तरां में इन सभी को ''दाल फ्राय'' का लेबल चस्पां कर खिलाया जाता है। तड़का या बघार तो हर दाल में लगाने का रिवाज है। दाल को फ्राय करने या तलने वाली प्रक्रिया असमंजस ही पैदा करती है। अंकुरित दालें अधिक पौष्टिक समझी जाती हैं और गुजरात-महाराष्ट्र में ''ऊसल'' तथा ''मिसल'' के रूप में इनका उपयोग पारंपरिक है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चने को अंकुरित कर गरीब परिवार नाश्ता तैयार होता है। यहीं सत्तू का जिक्र भी जरूरी है जिसे आमतौर पर चने को भूनकर तैयार किया जाता है और जिसे संपूर्ण आहार समझा जाता है। साधन हों तो इससे ''मखुनी'' नामक पराठा भी बनाया जा सकता है और गुड़ मिलाकर शरबत भी। चने की दाल से निर्मित बेसन से बनाए जाने वाले व्यंजनों की सूची बहुत लंबी है, जैसे कढ़ी, गट्टों, ढोकला, धोखा, लड्डू, बर्फी बगैरह। क्या आप पापड़, बड़ी, मंगोडी की कल्पना दाल को भुलाकर कर सकते हैं? दालमोठ हो या तली मूंग या चने की दाल यह सभी दर्शाते हैं कि दाल से बने पदार्थ हमारे भोजन का अभिन्न अंग रहे हैं।

अलबरूनी ने हजार साल पहले जब भारत का लंबा दौरा किया था यह पाया कि औसत भारतीय का दैनिक आहार दलियानुमा खिचड़ी ही था। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालिए कि खिचड़ी मजबूरी में नीरस आहार है। बंगाल की भुनी खिचुड़ी हो या मकर संक्रांति के पर्व पर पकाई जाने वाली माष की खिचड़ी अथवा दक्षिण भारतीय पोंगल, इन सभी में दाल ही जान डालती है। एक मजेदार बात यह है कि देश के विभिन्न सूबों में अलग-अलग दालें लोकप्रिय हैं। कहीं अकेली तो कहीं मिलीजुली। अरहर अथवा तुअर उत्तर दक्षिण में लगभग समान रूप से चाव से खाई जाती है पर राजस्थान में बाटी का साथ निबाहती है पंचमेल दाल। बंगाल में भुनी सोनार मूंग की दाल तथा छोलार (चना) दाल आम है जिसे लौकी, नारियल, किशमिश डाल कर पकाते हैं। उत्तराखंड में भट (काले सोयाबीन) की चुटकाणी लोहे की कढ़ाई में पकाई जाती है जिसे असाधारण रूप से पौष्टिक समझा जाता है। अवध में धुली उरद की ''खिलवां'' दाल सूखी नफासत का प्रतीक है तो मिट्टी के शिकोरे में फिरनी की तरह जमी मसूर की दाल ठंडी ही खमीरी रोटी के साथ पेश की जाती है। इसी भूभाग में पालक के सात पकाई दाल को ''सगपैता'' कहते हैं। अरहर की दाल कभी अमिया के साथ तो कभी गुड़ के साथ पकाई जाती है। रुहिलखंड में मुरादाबादी दाल प्रकट होती है जो मूंग की दाल को घोटकर तैयार की जाती है। हैदराबाद के निजामी दस्तरखान में मिली ''केवटी'' दाल सात बार अलग-अलग बघार लगाकर मेहमानों को चकित करती थी। वहीं गोश्त या कद्दू-लौकी के साथ ''दालचा'' भी बस्तों की पसंद है। हिमाचल प्रदेश में धाम नामक पारंपरिक सात्विक भोज में लगभग सभी व्यंजन दालों से तैयार होते हैं- राजमा, काबुली चने प्रमुख स्थान पाते हैं।

दालों के उपयोग की यह सूची बहुत लंबी है। कुछ दालें मौसम के अनुसार पचने में हल्की या भारी समझी जाती हैं। दो पीढ़ी पहले तक घर में गृहणियां इस पारंपरिक ज्ञान के अनुसार ही दालें पकाती थीं। आज विज्ञापनों के दबाव में हम उन दालों की तरफ लपकने लगे हैं जिन्हें अतिरिक्त पोषक तत्व से समृद्ध किया गया है। कुछ दालों को पकाने के पहले कुछ समय तक भिगोना जरूरी है। इससे ईंधन की बचत तो होती ही है, कुदरती स्वाद भी बरकरार रहता है।

भारतीय शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड में तीन विशाल ब्लैक होलों की खोज की

भारतीय शोधकर्ताओं ने तीन आकाशगंगाओं से तीन सुपरमैसिव ब्लैक होलों की खोज की है। ये आपस में एक साथ मिलकर एक तिहरा सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (न्यूक्लियस) बनाते हैं। नई खोजी गई आकाशगंगा के केंद्र में एक सघन क्षेत्र है जिसमें सामान्य से बहुत अधिक चमक है।

हमारे आस-पास के ब्रह्मांड में यह दुर्लभ घटना बताती है कि छोटे-छोटे आपस में मिलने वाले समूह कई साथ में बनने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाने के लिए आदर्श प्रयोगशाला हैं। इस तरह की चीजें ऐसी और भी दुर्लभ घटनाओं का पता लगाने की संभावना को बढ़ाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि वे कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। लेकिन वे अपने परिवेश के साथ परस्पर प्रभाव से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। जब आसपास से धूल और गैस एक सुपरमैसिव ब्लैक होल पर गिरती है, कुछ भाग ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाता है। इसमें से कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित होता है जिससे ब्लैक होल बहुत चमकदार दिखाई देता है।

कोरोनावायरस के अलग-अलग वेरिएंट से बचा सकती है एंटीबॉडी

एंटीबॉडी कोविड-19 वायरस के अलग-अलग वेरिएंट से आपको बचा सकते हैं । आज कोविड-19 के वायरस ने अपने आप में कई तरह के बदलाव कर लिए है, यह अब वैसा नहीं रहा जैसा कि दिसंबर 2019 में था। अब फैलने वाले कोरोना वायरस के रूप कई प्रकार के हैं, कुछ एंटीबॉडी आधारित चिकित्सा के लिए आंशिक रूप से प्रतिरोधी हैं। जैसे-जैसे महामारी आगे बढ़ती रहेगी, इस वायरस के कई रूप सामने आएंगे और इससे केवल प्रतिरोध की समस्या बढ़ेगी।सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने एक एंटीबॉडी की पहचान की है जो संक्रमित वेरिएंट की एक लंबी श्रृंखला के खिलाफ कम खुराक पर अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा, एंटीबॉडी वायरस के एक हिस्से से जुड़ जाता है जो थोड़ा भिन्न होता है, जिसका अर्थ है कि इस स्थान पर प्रतिरोध उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

क्या सदी के अंत तक बदल जाएगा समुद्र की सतह का 95 फीसदी हिस्सा

ललित मौर्य

यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अभी ठोस कदम न उठाए गए तो सदी के अंत तक समुद्री सतह का करीब 95 फीसदी हिस्सा बदल चुका होगा।

वैज्ञानिकों की मानें तो यदि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अभी ठोस कदम न उठाए गए तो सदी के अंत तक समुद्री सतह का करीब 95 फीसदी तक हिस्सा बदल चुका होगा। यह जानकारी हाल ही में एनओएए और उसके सहयोगियों द्वारा किए शोध में सामने आई है, जोकि जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्टस में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों की मानें तो कितनी समुद्री सतह की जलवायु में बदलाव आएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य में वैश्विक स्तर पर कितना उत्सर्जन होगा। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने 35.6 फीसदी से 95 फीसदी हिस्से की जलवायु में बदलाव आने की सम्भावना व्यक्त की है। इस शोध से यह भी पता चला है कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में बदलाव का खतरा सबसे ज्यादा है।

यहां समुद्री सतह की जलवायु से वैज्ञानिकों का मतलब सतह पर पानी के तापमान, अम्लता और अर्गोनाइट की मात्रा से है। देखा जाए तो समुद्री जीवों के दृष्टिकोण से अर्गोनाइट बहुत मायने रखता है, यह बड़ी संख्या में समुद्री जीवों का आधार होता है। इसका उपयोग समुद्री जीव अपनी हड्डियों और खोल को बनाने के लिए करते हैं।

क्यों आ रहे हैं यह बदलाव

समुद्री सतह की जलवायु में आने वाले बदलावों को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर महासागर की जलवायु का एक मॉडल तैयार किया है। जिसमें उन्होंने इसे तीन अवधियों, 19 वीं शताब्दी की शुरुवात (1795 से 1834), 20 वीं शताब्दी के अंत (1965 से 2004) और 21 वीं सदी के अंत यानी (2065 से 2104) के बीच बांटकर अध्ययन किया है। जलवायु में आ रह बदलावों को जानने के लिए उन्होंने उत्सर्जन के दो परिदृश्यों, आरसीपी 4.5 और आरसीपी 8.5 का उपयोग किया है और इसके आधार पर जलवायु में आने वाले बदलावों को समझने का प्रयास किया है। इस मॉडलिंग के निष्कर्ष से पता चला है कि 19 वीं और 20 वीं शताब्दी में जो जलवायु थी वो 21 वीं सदी में पूरी तरह बदल चुकी है। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच समुद्र की जलवायु में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आए थे। वहीं शोध के मुताबिक 21 वीं शताब्दी के अंत तक समुद्र की सतह का 81.9 फीसदी तक हिस्सा भविष्य में पूरी तरह एक नई जलवायु का अनुभव करेगा, जैसी जलवायु पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। इस नई जलवायु में तापमान और अम्लता पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होंगें और अर्गोनाइट की मात्रा काफी घट जाएगी। इस तरह यह नई जलवायु जीवों के लिए नई चुनौतियों को पैदा करेगी।

शोधकर्ताओं के अनुसार इन सबके लिए काफी हद तक वैश्विक स्तर पर होता उत्सर्जन जिम्मेवार है जिसकी वजह से जलवायु में बदलाव आ रहे हैं। अनुमान है कि आरसीपी 4.5 के तहत समुद्र की सतह के करीब 35.6 फीसदी हिस्से में जलवायु बदल जाएगी जबकि आरसीपी 8.5 के तहत यह बदलाव 95 फीसदी हिस्से में दिखाई देंगें। गौरतलब है कि आरसीपी 8.5 का मतलब है कि उत्सर्जन जैसे बढ़ रहा है उसका बढ़ना भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा।

क्या होगा इसका प्रभाव

शोध से पता चला है कि जिस तरह धरती पर जलवायु में बदलाव आ रहा है उसका असर समुद्र और वहां रहने वाले जीवों पर भी पड़ रहा है। इससे उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है।

नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी से जुड़ी और इस शोध की प्रमुख शोधकर्ता केटी लोटरहोस ने इसके प्रभाव के बारे में बताया कि बढ़ते कार्बन प्रदूषण के कारण समुद्र की संरचना में बदलाव आ जाएगा, जिसका असर सतह की सभी प्रजातियों पर पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो समुद्र में रहने वाली कई प्रजातियां तापमान और अम्लता में होने वाली वृद्धि से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करने के काबिल होती हैं।यहीं नहीं कुछ अपनी आदतों में बदलाव करके भी इससे बच जाती हैं। पर जब हर जगह तापमान और लवणता में वृद्धि हो जाएगी तो उनके लिए भी भविष्य में इससे बचना और तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन प्रजातियों के पास इस बदलती जलवायु को अपनाने या फिर मरने के आलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा।

उत्तराखंड में तीन दिन में 400 फीसदी अधिक बारिश, भारी नुकसान

एजेंसियां : उत्तराखंड में इस साल जलवायु परिवर्तन का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, राज्य में सामान्य से कम बारिश होने के बावजूद भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी

देहरादून में जाखन नदी का जलस्तर बढ़ने से ऋषिकेश-देहरादून मुख्य मार्ग पर बना पुल टूट गया। उत्तराखंड के कुछ जिलों में पिछले 60 घंटे से ज्यादा समय से लगातार हो रही बारिश से इन जिलों में भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन से सड़कें बंद हो रही हैं और पुलों को भी नुकसान हुआ है। देहरादून और टिहरी जिलों में जहां इन तीन दिनों में सामान्य से 400 प्रतिशत तक ज्यादा बारिश दर्ज हुई, वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी और अल्मोड़ा जैसे जिलों में बारिश हुई ही नहीं है।

देहरादून हाल के दिनों में बारिश के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अपेक्षाकृत सूखी रहने वाली जाखन नदी में 27 अगस्त की सुबह जबरदस्त जल सैलाब आने से देहरादून-ऋषिकेश राजमार्ग पर रानीपोखरी के पास बना पुल बह गया। रात को जाखन नदी के कैचमेंट एरिया मसूरी और सहस्त्रधारा क्षेत्र में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। मसूरी में 239 मिमी और सहस्त्रधारा क्षेत्र में 139 मिमी बारिश हुई। इससे पहले 25 अगस्त को भी सहस्त्रधारा और मसूरी क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी। सहस्त्रधारा में 254 और मसूरी में 112 मिमी बारिश हुई थी। 25 अगस्त से लेकर अब तक इस देहरादून जिले के इस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन दर्जनभर बस्तियों में मलबा घुसने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है।

छोटे और मझोले पोल्ट्री फार्मों के लिए सीपीसीबी की गाइडलाइन प्रदूषण रोकने के लिए उठाने होंगे कदम

नई गाइडलाइन में प्रमुख प्रावधान

- गैसीय उत्सर्जन और मल-मूत्र व कचरा पोल्ट्री की एक बड़ी समस्या है। पोल्ट्री पक्षियों के मल से अमोनिया (एनएच3) और हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2एस) का गैसीय उत्सर्जन होता है जो कि गंध पैदा करता है। एक ही जगह पर लंबे समय के लिए मल को एकत्रित करने से मीथेन गैस गंध के साथ पैदा होती है। ऐसे में छोटे और मध्यम पोल्ट्री को इन सब बातों का अब ध्यान रखना होगा।
- गाइडलाइन में कहा गया है कि पोल्ट्री से होने वाली गैसीय प्रदूषण को कम करने के लिए हवादार कमरा होना चाहिए। साथ ही पोल्ट्री की खाद (मैन्योर) बहते हुए पानी या किसी अन्य कीटनाशक से न मिलने पाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं, पोल्ट्री में मर जाने वाले पक्षियों को रोजाना हटाना और बिना पर्यावरण नुकसान पहुंचाए दफनाने के लिए भी जोर दिया गया है। मसलन भू-जल स्तर से तीन मीटर ऊपर दफन करना चाहिए।
- फार्म में बड्र्स के बीच उचित दूरी बनाने और चूहे और मक्खियों से बचाव के लिए भी उचित प्रबंध करने को कहा गया है।
- चारे की मिक्सिंग और उन्हें तैयार करते समय उड़ने वाली धूल भी लोगों को परेशान करती है। इसके लिए एक कक्ष ऐसा गेट पर ही बनाना होगा जहां मिक्सिंग के दौरान धूल न उड़े।
- छोटे और मध्य्म आकार वाले पोल्ट्री फार्म के किसानों को खाद की व्यवस्था करनी होगी। मसलन छोटे पोल्ट्री में कंपोस्टिंग और मध्ययम आकार वाले कंपोस्टिंग के साथ बायोगैस की व्यवस्था भी करनी होगी।
- पोल्ट्री में पानी का इस्तेमाल करने के बाद उसे टैंक में एकत्र करना होगा। इस पानी का इस्तेमाल बागबानी में करने का सुझाव दिया गया है।
- राज्य और जिला स्तर पर गाइडलाइन पालन कराने की जिम्मेदारी एनिमल हसबेंडरी डिपार्टमेंट की होगी।

पोल्ट्री स्थापित करने का दायरा : *●आवासीय इलाके से 500 दूर ●नदी, झील, नहर और पेयजल स्रोतों से 100 मीटर की दूरी ●राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर और गांव की पगडंडी व ग्रामीण सड़क से 10-15 की दूरी*

विवेक मिश्रा

छोटे और मध्यम आकार वाले करीब 25 करोड़ से अधिक पोल्ट्री को भी चारे में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की रोकथाम पर ध्यान देने की बात कही गई है।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश में पांच हजार से ज्यादा और एक लाख से कम बर्ड रखने वाले पोल्ट्री फार्म भी अब एक नई गाइडलाइन के तहत रेग्युलेटेड दायरे में रहेंगे। इस छोटे और मध्यम आकार वाली इंडस्ट्री को हरित श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में बड़े किसानों की तरह छोटे और सीमांत किसानों को भी पोल्ट्री से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने होंगे। वर्ष 2015 की संक्षिप्त गाइडलाइन के बाद पहली बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अगस्त, 2021 में विस्तृत और विविध पक्षों को शामिल करते हुए गाइडलाइन जारी की है।

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि एक ही जगह पर मध्यम आकार यानी 25 हजार से एक लाख बर्ड तक की संख्या वाली पोल्ट्री स्थापित और संचालित करने के लिए संबंधित पोल्ट्री को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति से जल कानून 1974 और वायु कानून, 1981 के तहत कंसेंट टू इस्टेबलिशमेंट (सीटीई) या कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) का प्रमाण-पत्र भी लेना होगा। यदि हरित श्रेणी में कोई पोल्ट्री होगी तो अनुमति 15 वर्षों के लिए मान्य होगी। देश में पोल्ट्री फॉर्म में पक्षियों की संख्या के हिसाब से पहली बार तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। इन तीन श्रेणियों में छोटे और लघु स्तर के पोल्ट्री फॉर्म को सप्ष्ट किया गया है।

1 स्मॉल कटेगरी 5 से 25,000
2 मीडियम कटेगरी 25,000 से अधिक और 100,000 से कम
3 लार्ज कटेगरी 100,000 से अधिक

20वें लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक देश में 85.18 करोड़ (851.8 मिलियन) पोल्ट्री पॉपुलेशन है। इसमें करीब 30 फीसदी (25 करोड़) बैकयार्ड पोल्ट्री है। पोल्ट्री सेक्टर में संगठित क्षेत्र करीब 80 फीसदी है और असंगठित क्षेत्र करीब 20 फीसदी है। दरअसल असंगठित क्षेत्र को बैकयार्ड पोल्ट्री भी कहकर पुकारा जाता है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 5 से 25000 की संख्या वाली पोल्ट्री यानी बैकयार्ड पोल्ट्री को ज्यादातर आर्थिक पिछड़े और असंगठित क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसान संभालते हैं। इनमें ज्यादातर वह खुद के उपभोग के लिए बर्ड रखते हैं और उनके पास एक छोटी सी मात्रा व्यावसायिक बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। ग्रामीण और आदिवासी किसानों के जरिए मुक्त दायरे या बैकयार्ड या सेमी इंटेसिव सिस्टम के तहत पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों को रूरल पोल्ट्री फार्मिंग कहकर पुकारा जाता है। रूरल पोल्ट्री फार्मिंग गरीब से भी गरीब किसानों के लिए भरण-पोषण का अतिरिक्त साधन भर है। पोल्ट्री सेक्टर में ज्यादातर छोटे और मध्यम किसान मुख्य रूप से कांट्रेक्ट फॉर्मिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 19वें लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक ऐसे किसानों की संख्या करीब 3 करोड़ है।

सीपीसीबी ने पोल्ट्री, हेचरी और पिगरी यानी पक्षियों, अंडे और सूकर पालन को हरित श्रेणी में रखा था। इसके बाद पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी मुलेखी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में 2017 में गाइडलाइन पर आपत्ति करते हुए यह मामला उठाया। उनका कहना था कि पॉल्ट्री फार्म पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए छोटे पोल्ट्री फार्म (5 हजार से अधिक पक्षी वाले) भी रेग्युलेटेड होने चाहिए। मामले में एनजीटी ने 16 सितंबर, 2020 को अपने आदेश में कहा कि "सीपीसीबी को पोल्ट्री फॉर्म को हरित श्रेणी में रखने और वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण कानून से मुक्त रखने वाली गाइडलाइन को रीविजिट करना चाहिए। यदि गाइडलाइन तीन महीने में जारी नहीं होती है तो एक जनवरी, 2021 से सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समिति संचालन अनुमति प्रक्रिया (कंसेट मैकेनिज्म) का पालन करेगी। ऐसे सभी पोल्ट्री फॉर्म जो 5000 बर्ड से ज्यादा रखती हैं उनके लिए संचालन की अनुमति की प्रक्रिया वहीं होनी चाहिए जो कि एक लाख से अधिक पक्षियों के रखने पर है।"

पोल्ट्री फार्म में मीट और अंडों के लिए चिकन, टर्की, बत्तख, गूज आदि का पालन किया जाता है। ब्रीडिंग के अलावा जो चिकन अंडे के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें लेयिंग हेन्स या लेयर्स करते हैं और जो चिकन मीट के लिए तैयार होते हैं उन्हें ब्रॉयलर्स कहते हैं। पोल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा चिकन की संख्या होती है। वर्ष 2020 लाइवस्टॉक सेंसस के मुताबिक कुल 85 करोड़ पोल्ट्री में सर्वाधिक पोल्ट्री तमिलनाडु (12.07 करोड़), आंध्र प्रदेश (10.78 करोड़), तेलंगाना (7.99 करोड़), पश्चिम बंगाल (7.73 करोड़), महाराष्ट्र (7.42 करोड़), कर्नाटक (5.94 करोड़), असम (4.67 करोड़), केरल (2.97 करोड़) में है। किसानों की आय को 2022 तक बढ़ाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर एग एंड पोल्ट्री-2022 रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में कुल पोल्ट्री की संख्या 72 करोड़ थी। इनमें 23 करोड़ बैकयार्ड पोल्ट्री थी। पोल्ट्री फार्मिंग बढ़ रही है और इसका पर्यावरणीय खतरा भी बढ़ रहा है।

इमर्जिंग झारखंड आयोजन में झारखंड के मुख्य सचिव ने कहा

झारखंड के कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी

नई दिल्ली : इनवेस्टर मीट के आयोजन इमर्जिंग झारखंड में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि मैं हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाते निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि राज्य की कार्यपालिका तक आपकी पहुंच आसानी से होगी। यहां प्रोएक्टिव अप्रोच से काम करनेवाले अधिकारी हैं, जो समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नीति के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की समस्या का सामना निवेशकों को नहीं करना पड़ेगा। झारखण्ड निवेशकों के लिए सबसे बेहतर अवसर है। निवेशकों के प्रति सरकार का रवैया दुनियाभर में बदला है। आज 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने टॉप ब्यूरोक्रेट के साथ निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंबी दूरी तय कर दिल्ली पहुंचे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। ऐसा संभव हुआ है, क्योंकि लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि किसी देश और राज्य के विकास की दास्तां तकनीक के विकास, रोजगार के सृजन से ही संभव है। झारखण्ड एक खूबसूरत राज्य है। फ्लोरा एवं फोना से भरा पड़ा राज्य है। 30 प्रतिशत हिस्सा जंगल से भरा है। बड़ी मात्रा में यहां वनोपज का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य का मौसम देश के बाकी हिस्सों से कहीं बेहतर है। अच्छे वातावरण से मानव संसाधन की क्षमता बढ़ जाती है। झारखण्ड में स्वस्थ और नियम से चलने वाले मानव संसाधन उपलब्ध हैं। झारखण्ड आपको आमंत्रित करता है। झारखण्ड आप सभी का स्वागत करता है।

सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार है: उद्योग सचिव

उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि झारखंड सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास 1000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। उन्होंने निवेशकों को झारखण्ड में क्यों निवेश करें से संबंधित विभिन्न आयामों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। जेआईआईपी, इथनॉल पॉलिसी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वेकिल पॉलिसी, आदित्यपुर क्लस्टर के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को सोलर पार्क, ऑटो हब, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का हब बनाने के लिए सरकार सभी निवेशकों को आमंत्रित कर रही है।

इस मौके पर विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव एल. खिंग्याते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, रेसिडेंशियल आयुक्त मस्तराम मीणा, सचिव अविनाश कुमार , मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह एवं उद्योगपति एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यूपी में गन्ने की खेती में ट्रेंच विधि से हो रहा जल संरक्षण

दीपान्विता गीता नियोगी

उत्तरप्रदेश में गन्ने की सिंचाई के लिए पानी की काफी खपत होती है। नदी से पानी निकालने की वजह से गन्ना उत्पादन वाले इलाकों में कई नदियों के सूखने की भी रिपोर्ट आई है। कुछ किसान गन्ने की खेती के लिए कम पानी की खपत वाला तरीका अपना रहे हैं। इस तरीके को ट्रेंच विधि कहते हैं। कुछ जिलों में किसानों ने 2017 से ही इसे अपनाना शुरू कर दिया।इस तरीके से उत्तरप्रदेश के 300 किसानों ने गन्ने की फसल में पानी की खपत कम की है जिससे वर्ष 2019 से 2021 के बीच छः करोड़ लीटर पानी की बचत हुई है।

उत्तरप्रदेश के बिजनौर जिले के खानपुर गांव के निवासी नरेंद्र कुमार बीते दो दशक से गन्ने की खेती करते हैं। वह कहते हैं, ''मेरे पिता ने बेहतर आमदनी के लिए गन्ने की खेती शुरू की। अभी हमलोग करीब 3.23 हेक्टेयर खेत में गन्ने की खेती करते हैं। पर बीते कुछ सालों में पानी की खपत को देखते हुए नरेंद्र कुमार ने गन्ने की खेती का तरीका बदला है। अब वे ट्रेंच विधि से खेती कर रहे हैं ताकि कम से कम पानी की जरूरत हो। इसमें पतली नाली के डिजाइन में एक सिरे से दूसरे सिरे में खुदाई होती है और किनारे किनारे मेढ बनाये जाते हैं।

उत्तरप्रदेश के 15 जिलों में 22.34 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। हमारे

गांव में 70 प्रतिशत किसान गन्ने की खेती करते हैं। मैंने ट्रेंच तकनीक से चार साल पहले खेती करना शुरू किया। इसकी मदद से 18 फीसदी तक पानी की बजत होने लगी।

कुमार की तरह गांव के कुछ और किसानों ने ट्रेंच विधि को अपनाया। पारंपरिक सिंचाई के तरीके में पानी को खेत तक पहुंचाने में काफी बिजली की आवश्यकता होती थी। करुला नदी के आसपास खेती करने वाले 300 किसानों ने यह तरीका अपनाया और बचा हुआ पानी नदी में वापस छोड़ने लगे। करुला रामगंगा नदी की सहायक नदी है। करुला नदी की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अक्टूबर और जून के महीने में नदी का बहाव खत्म हो जाता था। उत्तर प्रदेश में फ्लड इरिगेशन के बदले ट्रेंच विधि से खेती की शुरुआत 10 साल पहले हो गई थी। हालांकि, किसानों में तब इस पद्धति को अपनाने को लेकर हिचकिचाहट थी।

नदी का संरक्षण

गंगा की सहायक नदी रामगंगा उत्तरप्रदेश की एक बेहद प्रदूषित नदी मानी जाती है। नदी बचाने के लिए डब्लूडब्लूएफ इंडिया ने कृषि में पानी की खपत कम करने का प्रयास शुरू किया। गन्ना किसानों को नहरों के जरिए पानी पहुंचता है जिससे उन्हें सिंचाई में आसानी होती है। कई बार सिंचाई के दौरान पानी की बर्बादी भी होती है।खेती में पानी की खपत की वजह से देश की ज्यादातर नदियां गर्मी में दम तोड़ने लगती है। भारत में 80 प्रतिशत तक पानी खेती के काम में उपयोग होता है।

उभरती महिला हॉकी खिलाड़ी, संगीता कुमारी की द.पू.रेलवे मे नियुक्ति

संवाददाता आज दिनांक 27-08-2021 को मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा देश की एक उभरती हुई युवा महिला हॉकी खिलाड़ी, संगीता कुमारी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। संगीता कुमारी दक्षिण पूर्व रेलवे, रांची मंडल के कार्मिक विभाग मे जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त की गयी है।

जनवरी 2021 मे सैंटियागो, चिली मे आयोजित जूनियर महिला हॉकि टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन जूनियर भारतीय महिला हॉकि टीम थी तथा इस टीम मे संगीता कुमारी भी शामिल थी। इसके अलावा बैंकॉक में आयोजित यूथ ऑलिंपिक क्वालिफायर, बेल्जियम में आयोजित अंडर-23 6th Nation Invitatation Tour 2018, 7वां हॉकि इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2017 एवं 8वें हॉकि इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2018 में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर चुकी है।

संगीता कुमारी सिमडेगा की रहने वाली हैं तथा टीम में फॉरवर्ड स्थान पर खेलती एवं वर्तमान में बैंगलोर, कर्नाटक में चल रहे जूनियर भारतीय महिला हॉकि टीम के कैम्प में शामिल है । इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मंडल क्रीड़ा अधिकारी अवनीश, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री माणिक शंकर, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुमराय टेटे , भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं भारतीय महिला हॉकि टीम की पूर्व कप्तान श्रीमति असुंता लकड़ा एवं दक्षिण पूर्व रेल्वे खेल संघ रांची के समन्वयक श्री प्रशांत मुखर्जी उपस्थित थे।

नदी की धारा मोड़ने का विरोध, आंदोलनकारियों पर सख्ती

खरेसोतरा नदी भितरकनिका इस उद्यान के करीब से गुजरती है। परियोजना के चलते खारे पानी के बढ़ने और खाड़ी में मगरमच्छों की आबादी पर असर पड़ने के कारण भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओडिशा में नदी का रुख बदलने का विरोध कर रहे लोगों को सख्ती कर हटाया, अस्पताल में भर्ती। राज्य सरकार ने एक परियोजना के लिए खरेसोतरा नदी के पानी का रुख बदलने का विरोध करने पर एक हजार मामले दर्ज कराए और 24 लोगों को गिरफ्तार किया

हैआशीष सेनापति

ओडिशा के केंद्रापाड़ा जिले में दस अगस्त 2021 से खरोसोतरा नदी के पानी का रुख बदलने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता श्रीकांत नायक को विरोध-स्थल से हटाकर 25 अगस्त को कटक अस्पताल के बाहर डाल दिया गया। श्रीराम चंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

सेंटर फॉर पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडवोकेसी के चेयरमैन व संस्थापक और युवा ओडिशा फाउंडेशन के संस्थापक तेजेश्वर परिदा इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, ' मैं नायक से केंद्रापाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल में 25 अगस्त की सुबह मिला था। शाम को उन्हें जबरदस्ती कटक के श्रीराम चंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। अस्पताल में उस समय काफी भीड़ थी और कोई बेड उपलब्ध नहीं था। उन्हें अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे सोना पड़ा। बाद में पता चला कि 26 अगस्त को उन्हें अस्पताल के मेडिकल वार्ड में लिया गया। 45 साल के नायक केंद्रापाड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास दस अगस्त से इस परियोजना का विरोध कर रहे थे।

खरोसोतरा नदी

754 करोड़ की यह वृहद पेयजल परियोजना राज्य सरकार की है। इसके तहत केंद्रापाड़ा जिले के खरोसोतरा नदी के पानी का रुख बदला जाना है। इस फैसले से पड़ोसी भद्रक जिले के पांच लाख लोग प्रभावित होंगे। भद्रक के चार ब्लॉकों की 91 ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों पर इसका असर पड़ना है। गौरतलब है कि पानी का रुख पेयजल के मकसद से बदला जाना है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से नदी के जिस हिस्से का पानी सूखेगा, उसके करीब के 220 गांवों की खेती बर्बाद हो जाएगी। केंद्रापाड़ा जिले के अल और राजकनिका नाम के दो ब्लॉकों के आसपास के गांवों में करीब चार लाख लोग रहते हैं।

नायक एक गैर-लाभकारी संगठन 'संभाबना' के कार्यकर्ता हैं, जो इस परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भागीदार है। 16 अगस्त को अधिकारियों ने उन्हें विरोध-स्थल से हटाकर जिला मुख्यालय के अस्पताल भेज दिया था क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। हालांकि उन्होंने वहां खाना खाने से मना कर दिया था और अपनी भूख हड़ताल जारी रखी थी। देश के 'जलपुरुष' नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह ने उनसे 24 अगस्त को केंद्रापाड़ा में मुलाकात की थी। सिंह ने कहा, 'उस नदी-क्षेत्र से पानी का रुख बदलना, जिसमें पहले से पानी की कमी है, उस इलाके में समुद्र के पानी के आने की संभावना को को बढ़ाएगा, जिससे जिले की खेती चौपट होगी। इस परियोजना से नदी किनारे के गांवों में रहने वाले लोगों को मीठे पानी की कमी से जूझना पड़ेगा और साथ ही उन्हें खारे पानी का खतरा भी होगा। '

परियोजना के विरोध में नदी किनारे के गांवों में रहने वाले लोगों ने 12 अगस्त को भारी तादाद में जुटकर मार्च निकाला और भरीगदा गांव में प्रस्तावित परियोजना स्थल तक गए। इस दौरान उन्होंने वहां कई वाहनों, एक डीजल टैंकर, एक एम्बुलेंस और तीन अन्य मशीनों के अलावा ग्रामीण जल वितरण एवं स्वच्छता के कैंप कार्यालय को नुकसान पहुंचाया। लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले भी किए। जवाब में पुलिस ने 13 अगस्त को 24 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

सेंटर फॉर पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडवोकेसी के चेयरमैन तेजेश्वर परिदा इस संकट का समाधान करने के लिए कई सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'परियोजना का काम तुरंत रोका जाना चाहिए। राज्य सरकार को पानी के संग्रह के लिए नदी पर बांध बनाने पर राजी होना होगा। उसे मुख्य सचिव, विकास आयुक्त या प्रमुख सचिव स्तर के किसी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनानी चाहिए। इस समिति में सरकार के वन, पर्यावरण, जलवायु-परिवर्तन, जल संसाधन, पेयजल विभागों के साथ ही अनय भागीदारों और पर्यावरण के लिए काम करने वालों, खासकर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जैसे मैंग्रोव परिक्षेतों में काम करने वाले को शामिल किया जाना चाहिए।

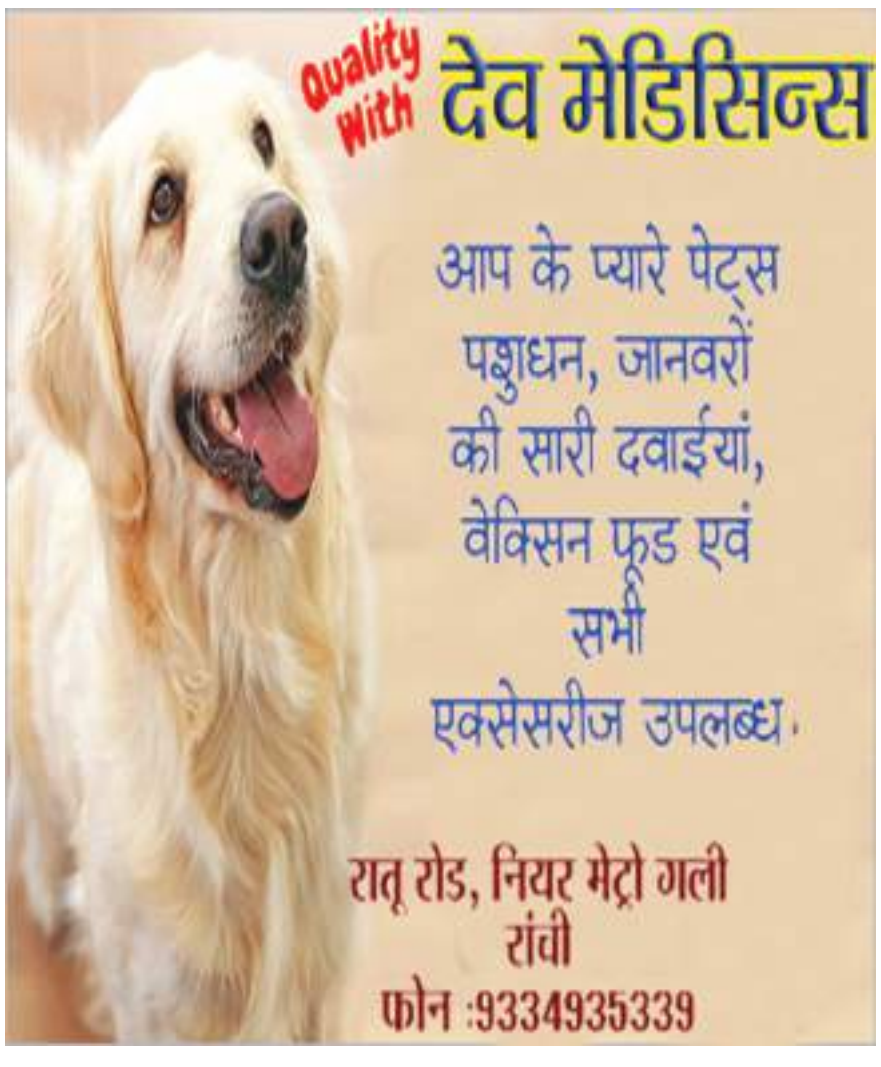

भारत के 21 फीसदी हिस्से पर मंडरा रहा है सूखे का खतरा

शगुन

इस साल सूखे की स्थिति का सामना कर रहा भूभाग पिछले वर्ष की तुलना में करीब 62 फीसदी ज्यादा है। 2020 में देश का करीब 7.86 फीसदी हिस्सा जैसी स्थिति का सामना कर रहा था

सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (डीईडब्ल्यूएस) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों को देखें तो भारत का पांचवां हिस्सा (21.06 फीसदी भूभाग) सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। देखा जाए तो सूखे का सामना करने वाला यह क्षेत्र पिछले साल की तुलना में करीब 62 फीसदी ज्यादा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान देश का करीब 7.86 फीसदी हिस्सा सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा था। आंकड़ों के अनुसार देश का जो 21.06 फीसदी हिस्सा सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है, वहां कहीं सूखे की स्थिति मध्यम और कहीं काफी गंभीर है। जहां 1.63 फीसदी क्षेत्र अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों का सामना कर रहा है, वहीं 1.73 फीसदी भूभाग असाधारण रूप से शुष्क है। 2.17 फीसदी गंभीर रूप से शुष्क है जबकि 8.15 फीसदी हिस्सा मध्यम रूप से शुष्क है। 16 अगस्त, 2021 को जारी नवीनतम इन आंकड़ों के अनुसार देश की करीब 7.38 फीसद भूमि असामान्य रूप से शुष्क है।

कई राज्यों में गंभीर बनी हुई है स्थिति

पिछले कुछ समय से देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बानी हुई है। वहीं पिछले दो महीनों में हुई बारिश के पैटर्न के आधार पर लगाए गए अनुमान के अनुसार राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और नागालैंड जैसे कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूखे की गंभीर से असाधारण स्थिति बनी हुई है। हाल ही में मिली जानकारी से पता चला है कि पश्चिमी राजस्थान में तो सूखे की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहां पाली जिले में जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन ट्रेन से पानी की सप्लाई पर विचार कर रहा है। इस जिले में सामान्य से 37 फीसदी कम बारिश हुई है और पूरे जिले को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध में केवल एक माह का पानी शेष बचा है। इस बारे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर विमल मिश्रा ने जानकारी दी है कि दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ मुश्किल वक्त का सामना कर रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों में मानसून के शेष भाग के दौरान वर्षा नहीं होती है, तो स्थिति और खराब हो सकती है। अनुमान है कि मौजूदा स्थिति के लिए वर्षा का असमान वितरण और मानसून का विफल होना मुख्य वजहों में से है।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से अधिकांश राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। 19 अगस्त तक जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में सामान्य से 48 फीसदी कम बारिश हुई है, वहीं ओडिशा में यह आंकड़ा 29 फीसदी है। नागालैंड और पंजाब दोनों राज्यों में सामान्य से 22 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 11 फीसदी और राजस्थान में सामान्य से चार फीसदी बारिश कम हुई है। पिछले एक महीने के दौरान मिट्टी में मौजूद नमी से जुड़े सूचकांक पर आधारित अनुमानों के अनुसार ओडिशा के कई जिले सूखे की चपेट में है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खरीफ फसल को बचाने के लिए राज्य सरकार पहले ही कृषि विभाग को आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश दे चुकी है।

तस्वीरों में टीम ग्रीन का रांची पहाड़ी पर वृक्षारोपण

पौधे लगाते टीम ग्रीन के युवा सदस्य

बच्चों ने भी बढ़ - चढ़ कर भाग लिया

रांची विधायक सीपी सिंह भी पहुंचे

पर्यावरणप्रेमियों कीऔर सप्ताहांत का आनंद लिया और आश्वासन दिया कि लक्ष्य पूरा हो गया है। इसके लिये टीम ग्रीन ने रांची जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति इस अभियान में भाग लेने और जागरूकता बढ़ाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों और स्वयंसेवकों , रांची के नागरिकों को पौधे लगाने के लिए धन्यवाद दिया है।

टीम ग्रीन रांची के सक्रिय व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें निपुण जैन जैसे युवओं की टीम है। जो पर्यावरण और प्रकृति की देखभाल करने के लिए समर्पित है। गोइंग ग्रीन, ग्रीन गोज़ उनका आदर्श वाक्य है, जो हर रविवार को वृक्षारोपण करता रहता है और पेड़ों के अस्तित्व को भी सुनिश्चित करता है। टीम हेल्प रांची एक पंजीकृत ट्रस्ट है और वर्तमान में रांची जिला प्रशासन के लिए वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन का प्रबंधन कर रही है। वे वृक्षारोपण अभियान, पुराना कपड़ा और भोजन वितरण, रक्तदान शिविर, नौकरी सहायता आदि जैसी सामाजिक कल्याण पहल भी करते हैं। संगठन ने अपना जमशेदपुर चैप्टर भी लॉन्च किया है और वृद्धाश्रम में पहला पुराना कपड़ा वितरण अभियान चलाया है। साथ ही सुविधाहीन बच्चों को पढ़ाने के लिए जल्द ही हेल्प एकेडमी शुरू की जाएगी।

फट सकता है बड़ा ज्वालामुखी, बदल सकता है जलवायु चक्र

भगीरथ श्रीवास

आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अगर ज्वालामुखी फटता है तो सतह का वैश्विक तापमान एक से तीन साल तक कम हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की छठी असेसमेंट रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के खतरे से आगाह कहते हुए कहा गया है कि इस सदी में बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। यह विस्फोट वैश्विक स्तर पर धरती की सतह का तापमान एक से तीन साल तक कम कर देगा। साथ ही, वैश्विक मॉनसून को भी प्रभावित करेगा और जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत से कारकों को बदल देगा।

अगर ऐसा विस्फोट होता है तो इसके लिए अस्थायी तौर पर मानवीय गतिविधियों से होने वाला जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार होगा। आईपीसीसी ने यह अनुमान जलवायु विज्ञान के विस्तृत अध्ययनों और ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लगाया है।रिपोर्ट के अनुसार, औद्योगिक काल से पहले विस्फोटक ज्वालामुखी जलवायु में बदलाव लाने के सबसे बड़े कारक रहे हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 2,500 सालों में -1W M-2 (वॉट वर्गमीटर) प्रभावी रेडियेक्टिव ताकत (ईआरएफ) से अधिक के ज्वालामुखी 100 सालों में दो बार फटते हैं। 1991 में पिनाटुबू में फटा ज्वामुखी इसका उदाहरण है । ऋणात्मक ईआरएफ वाले ज्वालामुखी में राख और धुआं अधिक रहता है जिससे जलवायु ठंडी होती है, जबकि सकारात्मक ईआरएफ वाले ज्वालामुखी गर्मी बढ़ाते हैं)।इस अवधि में -5ह -2 ईआरएफ वाले 8 बड़े ज्वालामुखी फटे हैं। 1257 में इंडोनेशिया के समालास पर्वत और 1815 में तंबोरा पर्वत पर फटा ज्वाालमुखी इसके उदाहरण हैं। समालास पर्वत जैसे ज्वालामुखी औसतन 1000 साल में एक बार फटते हैं। रिपोर्ट के अनुसार आमतौर हर 400 साल में तीन बार एक न एक ज्वालामुखी -1W m-2 ईआरएफ वाला होता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, बड़े ज्वालामुखी एक्सट्रीम ठंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और यह ठंड दशकों तक जारी रह सकती है। तंबोरा और समालास के ज्वालामुखी का असर वैश्विक तापमान पर पड़ा था। तंबोरा के ज्वालामुखी के बाद पर्वत की ऊंचाई 14,100 फीट से घटकर 10,000 फीट रह गई थी। इस ज्वालामुखी से निकली राख और धुआं उत्तरी गोलार्द्ध पर छा गया था जिससे सूरज की रोशनी धरती पर ठीक से नहीं पहुंच पाई और सतह का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया था। जिस साल ज्वालामुखी फटने की यह घटना हुई, उस साल गर्मियों का मौसम नहीं आया था। इसी वजह है 1815 को ''ईयर विदाउट समर'' कहा जाता है। उस साल दुनिया के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई थी और भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार, अध्ययन बताते हैं कि 21वीं शताब्दी के शुरुआती में संभावित ज्वालामुखी वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से कुछ समय के लिए रोक सकते हैं।

अप्रोच सड़क में लगे पत्थरों के दरार बने रसल्स वाइपर सापों के बसेरे

मनोकामना सिंह

मांझी(सारण): बिहार की सीमा में स्थित जयप्रभा सेतु के एप्रोच सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से चिपकाए गए बोल्डर के भीतर दुनिया के सबसे जहरीले सांप रसल्स वाइपर का जखीरा बन गया है। एप्रोच सड़क किनारे मिट्टी का क्षरण रोकने के उद्देश्य से किये गए बोल्डर पीचिंग के दरार के भीतर अपना बसेरा बना चुके अनगिनत रसल्स वाइपर दिन अथवा रात में विचरण करते अक्सर दिखते रहते हैं। जयप्रभा सेतु के अलावा रेल पुल के समीप बड़ी मात्रा में जमा किये गए बोल्डर के भीतर भी इन सांपों का जबरदस्त जखीरा है। मांझी बलिया मोड़ तथा मांझी चट्टी के बीच अक्सर ही दिख जा रहे जहरीले रसल्स वाइपर सांपों से लोग रात दिन दहशत में रहते हैं। लगभग एक दशक से इस इलाके में रसल्स वाइपर सांप दिख रहे हैं। इससे पहले गांव में गेंहूअन तथा करैत सांप ही ज्यादा दिखते थे। लेकिन अब वे सांप बिरले ही दिखते हैं।एप्रोच सड़क के किनारे कीड़े मकोड़े को अपना ग्रास बनाने के लिए रसल्स वाइपर रात में बड़ी संख्या में निकलते हैं इस वजह से ग्रामीणों तथा राहगीरों पर खतरा मंडराते रहता है। प्रतिदिन दो चार की संख्या में ये सांप वाहनों से कुचल कर मरते भी हैं। स्थानीय टी एन सिंह ने बताया कि गांव के आसपास दिखने वाले रसल्स वाइपर पांच छह फुट लंबे तथा लगभग पांच दस किलो वजन के भी होते हैं।

कई लोगों की इन सापों के काटने से मौत भी हो चुकी है। जय प्रभा सेतु के आसपास के गांव के लोगों का आरोप है कि सम्बन्धित विभागीय ठेकेदार द्वारा बोल्डर पीचिंग में अनियमितता बरती गई है जिस वजह से प्रतिवर्ष सरयु में आने वाली बाढ़ तथा बरसात में बोल्डर इधर उधर लुढ़क कर बेतरतीब ढंग से बिखरे रहते हैं। बिछाए गए बोल्डर के ऊपर झाड़ झंखाड़ का साम्राज्य बन गया है इसी वजह से यह इलाका रसल्स वाइपर सांपों का सुरक्षित रैन बसेरा बन गया है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

आर्किड की नई और दुर्लभ प्रजातियों की हुई खोज

शोधकर्ताओं ने बताया कि तीन वर्षों की निगरानी में, एल. माइक्रोप्रोसार्टिमा के केवल 40 पौधे पाए गए जिससे पता चलता है कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है।

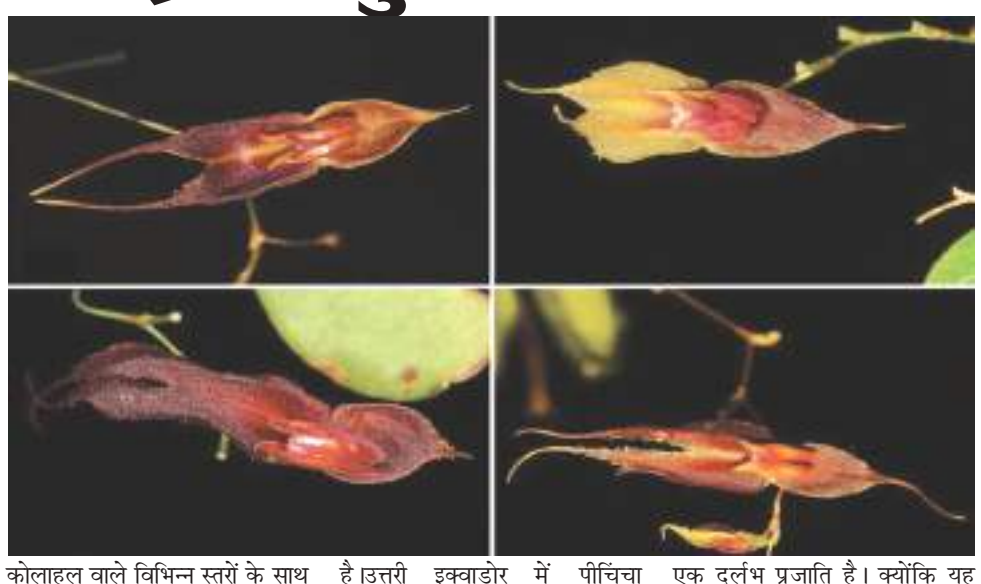

इक्वाडोर में काफी जैव विविधता पाई जाती है जो प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के एक अनूठे समूह को आश्रय देती है। उनमें से कई स्थानीय हैं जो अब खतरे में हैं। अधिक जैव विविधता होने के चलते अधिकांश अध्ययन अभी भी प्रजातियों की समृद्धि को रिकॉर्ड करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि ये प्रजातियां वास्तव में परस्पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि 2017 में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट, स्नो एंड लैंडस्केप रिसर्च के डॉ कैथरीन एच. ग्राहम ने यूरोपीय अनुसंधान परिषद और स्थानीय एनजीओ एस वाई कंजर्वेशन के समर्थन से, इक्वाडोर के उत्तर-पश्चिमी एंडीज में अध्ययन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। इसमें ऊंचाई वाली भूमि, ढाल के साथ पेड़-पौधे, चिड़ियों के परस्पर प्रतिक्रिया के बारे में पता लगाया गया है।इसके लिए, शोधकर्ताओं ने अच्छी तरह से संरक्षित जंगल के क्षेत्रों में और अलग-अलग ऊंचाई पर, कोलाहल वाले विभिन्न स्तरों के साथ 18 हिस्सों की स्थापना की। उन फूलों की गिनती करने के लिए मासिक दौरा किया जो चिड़ियों को आकर्षित करते हैं और फूलों और पौधों में टाइम-लैप्स कैमरे लगाए गए।

कार्य के दौरान कई नई प्रजातियों की खोज की गई, इस दौरान सर्वेक्षण और कैमरों द्वारा लगभग 400 पौधों की प्रजातियों की पहचान की गई। उनमें से एक नई आर्किड प्रजाति है जिसे लेपेंथेस माइक्रोप्रोसार्टिमा कहा जाता है, उसकी पहचान की गई है।उत्तरी इक्वाडोर में पीचिंचा ज्वालामुखी के पश्चिमी ढलानों पर पाया जाने वाला, एल. माइक्रोप्रोसार्टिमा यानाकोचा और वर्देकोचा रिजर्व के पास है। यह सदाबहार पर्वतीय जंगल समुद्र तल से 3200 से 3800 मीटर ऊपर है। उल्लेखनीय रूप से, यह प्रजाति जंगल की गहरी छाया में भी पनप सकती है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि तीन वर्षों की निगरानी में, एल. माइक्रोप्रोसार्टिमा के केवल 40 पौधे पाए गए, जिससे पता चलता है कि यह एक दुर्लभ प्रजाति है। क्योंकि यह केवल एक छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है, शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक रूप से आईयूसीएन मानदंडों के अनुसार इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में मूल्यांकन किया। उसी हमिंगबर्ड निगरानी परियोजना के अंतर्गत, पूर्वी पीचिंचा में एक और नया आर्किड - *लेपेंथेस कैरानक्वी* खोजा गया था। लगभग उसी समय, इक्वाडोर के पोंटिफिकल कैथोलिक विश्वविद्यालय के एक अलग शोध समूह ने इम्बाबुरा में इसकी एक ही प्रजाति का पता लगा पाई। जबकि इम्बाबुरा में यह सड़क के किनारे के तटबंधों पर छोटे समूहों के साथ, पैरामो में बढ़ता हुआ पाया गया। पीचिंचा में यह अन्य ऑर्किड प्रजातियों में, पेड़ की निचली शाखाओं के ऊपर सदाबहार पर्वतीय जंगल में विकसित हुआ। इसका नाम, लेपेंथेस कैरनक्वी, कारान्क्वी संस्कृति का सम्मान करता है जिसने ऐतिहासिक रूप से उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जहां यह पौधा उगता है। यह शोध जर्नल फाइटो कीज में प्रकाशित हुआ है।लेकिन इक्वाडोर की जैव विविधता के चमत्कार यहीं नहीं रुकते है, इक्वाडोर के राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान की एक शोध परियोजना को एल ओरो के दक्षिण-पश्चिम में 3 सेमी जितनी छोटी एक और नई प्रजाति मिली है। लेपनथस ओरो लोजेन्सिस वास्तव में एल ओरो और लोजा प्रांतों के बीच की सीमा पर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम इस तरह रखा गया। यह केवल एक इलाके से पाया गया था, जहां इसकी आबादी को पशुपालन, आग, विदेशी पौधों के वृक्षारोपण और जलाऊ लकड़ी के रूप में झाड़ियों के संग्रह से खतरा है। इसहलये शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे आईयूसीएन के अनुसार गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। **साभार : डीटीइ**

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।